रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड।

बनाम

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बड़ौदा

अप्रेल 26,1990

[एस. रंगनाथन और ए. एम. अहमदी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944/केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 : धारा 4,35 सी/पहली अनुसूची, मद 17, नियम 8 (1) और अधिसूचना संख्या। 24 1984 का 25,1984 का 25 और प्रावधान और 1985 का 45-उत्पाद शुल्क-कागज और पेपर बोर्ड पर रियायती दरें-अपवाद खंड-आर्ट पेपर और क्रोमो पेपर की व्याख्या-चाहे वह छूट का हकदार हो-समाज का सिद्धांत-समाज की प्रयोज्यता।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम (1) के तहत 1984 की अधिसूचना संख्या 24 और 25, केंद्रीय राजकोष और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद 17 (1) के तहत आने वाला कागज और कागज बोर्ड के संबंध में 1.3.1984 को जारी की गई थी। जबकि 1984 की अधिसूचना संख्या 24 ने कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क प्रतिबंधित किया। 1984 की अधिसूचना संख्या 25 में लुगदी से निर्मित कागज और कागज के बोर्डों के संबंध में रियायत का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामग्री (बांस, दृढ़ लकड़ी, सॉफ्टवुड, रीड्स या रग के अलावा) से बने लुगदी के

वजन द्वारा 50 प्रतिशत से कम नहीं है और किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके बाद मंजूरी दी जाती है, जो अधिसूचना के प्रावधानों में निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन है। प्रावधानों के तहत, रियायती दरें केवल तभी लागू होती थीं जब कारखाने में बांस, लकड़ी का गूदा बनाने के लिए संयंत्र नहीं होता था और छूट सिगरेट के ऊतक, कांच के कागज, ग्रीस प्रूफ पेपर, लेपित कागज (मोम वाले कागज सहित) और 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक के पदार्थ के कागज पर लागू नहीं होती थी। 1985 की एक अन्य अधिसूचना संख्या 45 दिनांक 17.3.1985 भी जारी की गई थी जिसमें लेपित कागज सहित उपरोक्त वस्तु के अंतर्गत आने वाले कागज और पेपर बोर्ड पर दरें निर्धारित की गई थीं।

अपीलार्थी-निर्धारिती का एक कारखाना था जिसमें विभिन्न प्रकार के कागज और पेपर बोर्ड का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अपशिष्ट कागज और अनाज के पुआल का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें अपरंपरागत कच्चे माल से बने गूदे का वजन 50 प्रतिशत से अधिक था। कारखाने में बांस के पल्प का पौधा नहीं था।

निर्धारिती आर्ट पेपर और क्रोमो पेपर का निर्माण कर रहा था। ये दो प्रकार के कागज आम तौर पर मुद्रण और लेखन कागज की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों वस्तुयें भी 1984 की अधिसूचना संख्या 25 के दूसरे परंतुक में उपयोग किये गये कागज लेपित कागज विवरण के अंतर्गत आते

हैं। अपीलार्थी ने शुरू में 1984 की अधिसूचना संख्या 24 के संदर्भ में अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया, लेकिन बाद में 1984 की अधिसूचना संख्या 25 द्वारा निर्धारित रियायती दरों का दावा किया। चूंकि लेपित कागज को 1984 की अधिसूचना संख्या 25 के दायरे से बाहर कर दिया गया था, इसलिए उत्पाद शुल्क विभाग ने निर्धारिती को अपने निर्मित सामानों के संबंध में इस छूट का लाभ उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसकी पुष्टि की।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया कि हालांकि 'लेपित कागज' अभिव्यक्ति का एक व्यापक अर्थ था और इसमें सभी प्रकार के लेपित कागज शामिल थे, लेकिन जिसमें यह परंतुक में दिखाई दिया संदर्भ में इसका एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए कि कागज के व्यवसाय में, कागज मोटे तौर पर दो प्रकार का था, "औद्योगिक कागज" और "सांस्कृतिक कागज", जबकि मुद्रण या लेखन के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज को सांस्कृतिक कागज के रूप में माना जाता था जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, जिसे मोटे तौर पर औद्योगिक शुद्ध मुद्राओं के रूप में वर्णित किया जाता था, जैसे कि लपेटना, पैकिंग, स्वच्छता उपयोग और इसी तरह, औद्योगिक कागज था, क्योंकि परंतुक में उल्लिखित सभी पांचों में एक प्रकार की समानता थी। श्रेणियां, जो कि पहली तीन किस्में हैं, स्वीकार्य रूप से औद्योगिक कागज

की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और अंतिम का उपयोग हमेशा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, और इसलिए ट्राइ बूनल द्वारा पाया गया कि 'लेपित कागज' शब्द को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, और इसकी व्याख्या 'नोसिटूर ए सोसाइटीज' के सिद्धांत को लागू करके या 'एजुस्डेम जेनरिस' सिद्धांत के सादृश्य पर की जानी चाहिए और यह कि भले ही परंतुक के शब्द व्यापक तरीके से माने जाने में सक्षम थे ताकि सभी प्रकार के लेपित कागज को छूट से इनकार किया जा सके, अदालत को कर कानूनों के निर्माण के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करना चाहिए कि एक अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या के पक्ष में की जानी चाहिए।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई व्याख्या का सिद्धांत नहीं था जिसके द्वारा 'लेपित कागज' शब्द के सरल और प्राकृतिक अर्थ को संक्षिप्त किया जा सकता था और न ही इस संदर्भ में ऐसी सीमा की गारंटी देने के लिए कुछ भी था, कि औद्योगिक और सांस्कृतिक कागज के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था, और यह नहीं कहा जा सकता था कि हल्का कागज केवल औद्योगिक कागज हो सकता है।

न्यायालय द्वारा, अपीलों को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया:-

1. 1984 का सं. 25 अधिसूचना के दूसरे परंतुक में 'कोटेड पेपर' केवल औद्योगिक शुद्ध मुद्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले लेपित

कागज को संदर्भित करता है न कि मुद्रण और लेखन कागज की लेपित किस्मों को। इसलिए, अपीलार्थी अधिसूचना में निर्दिष्ट रियायती दरों का हकदार है। (812 एफ-जी]

2.1 परंतुक में अभिव्यक्ति 'लेपित कागज' को उस संदर्भ में लेना चाहिए जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है और इसके शाब्दिक की तुलना में इसके अनुरूप एक व्याख्या प्राप्त करता है, जो अपने व्यापक अर्थों में, सभी लेपित कागज, औद्योगिक या अन्य को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो सकता है। [809 जी-एच]

2.2 अधिसूचना की रियायत को पाँच प्रकार के कागज के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। इनमें से तीन औद्योगिक कागज की किस्में हैं। चौथा हल्का कागज है, जो किसी विशेष वजन से अधिक नहीं है। हल्का कागज बड़े पैमाने पर औद्योगिक कागज होता है और इसका उपयोग कभी-कभी सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। 1985 की अधिसूचना संख्या 3 और 4 के और क्रम संख्या 1 और 3 में कागज की पाँच किस्में पाई जाती हैं जो सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले लेपित कागज और हल्के कागज के बीच एक अंतर को दर्शाता है (मद संख्या 1) और जिसका उपयोग अन्य (औद्योगिक) उद्देश्यों के लिए किया जाता है (मद संख्या 3)। इस आधार पर, यह स्पष्ट है कि कागज की पाँच किस्मों में से चार, जो रियायत के लाभ से वंचित हैं, औद्योगिक कागज हैं। वास्तव

में, भले ही इनमें से केवल तीन वस्तुएं औद्योगिक किस्म की हों, जबकि अन्य दो भी हो सकती हैं, फिर भी यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा (हालांकि, थोड़ा कम प्रशंसनीय हो सकता है) कि उन दो श्रेणियों में आने वाले केवल आैद्योगिक कागज का उद्देश्य वर्गीकरण में पूर्वनिर्धारित किया जाना है, न कि यह मान लेना कि अकेले इन दो किस्मों के सभी कागज रियायत से बाहर हैं। [809 ई-जी]

2.3 हालांकि कोई सावधानीपूर्वक कारण हमेशा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच शुल्क की दरों में भिन्नता के लिए खोजा गया और समान रूप से व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं के एक समूह के संबंध में कुछ समानता की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से वर्गीकरण को तर्कहीन या मनमाना नहीं बना सकती है। यह वैध रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि किसी समूह को रियायत से इनकार करना समूह के सभी मदों के लिए सामान्य कुछ पहलू या विशेषता के आधार पर आगे बढ़ता है। यदि ऐसे सिद्धांत की कल्पना की जा सकती है जिससे सभी वस्तुओं के समावेश को तर्कसंगत बनाया जा सके, तो अधिसूचना के निर्माण को प्रभावी बनाना काफी उचित और उचित होगा जो उस सिद्धांत के अनुरूप होगा। [808 एफ-जी]

2.4 किसी भी अधिसूचना के दायरे की व्याख्या करने में, न्यायालय सबसे पहले अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखें। इसके

सभी भागों को उस उद्देश्य की सहायता के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि अपमान के रूप में। [811 एफ]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, [1989] i एस. सी. सी. 345 और टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., [1989] 4 एस. सी. सी. 541 संदर्भित किया गया।

हस्तगत मामले में, अधिसूचना का उद्देश्य अपरंपरागत कच्चे माल के साथ कागज का निर्माण करने वाले छोटे पैमाने के कारखानों को रियायत देना है। यदि परंतुक में केवल लेपित कागज का उल्लेख किया गया होता तो कोई विशेष उद्देश्य या उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता और शायद इसके आगे देखने और यह अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं होता कि अधिसूचना में इन कारखानों द्वारा निर्मित केवल लेपित कागज को छूट के दायरे से छूट देने के बारे में क्यों सोचा जाना चाहिए था। लेकिन अधिसूचना में एक नहीं बल्कि वस्तुओं के एक समूह को शामिल किया गया है। यदि समूह में उल्लिखित वस्तुएं पूरी तरह से भिन्न थीं और उनमें किसी भी समानता को देखना असंभव था, तो फिर से, अपवादों को उनका सबसे विस्तृत परिप्रेक्ष्य देने की अनुमति हो सकती है। लेकिन जब उनमें से चार-निस्संदेह, उनमें से कम से कम तीन-को एक बोधगम्य वर्गीकरण के तहत लाया जा सकता है और यह भी कल्पना की जा सकती है कि सरकार ने अच्छी तरह से सोचा होगा कि इन छोटे पैमाने के कारखानों को अधिसूचना द्वारा विचारित

रियायत के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, जहां वे औद्योगिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कागज बनाते हैं, तो निर्धारित सीमा में एक उद्देश्य है और इस वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान पर तर्कसंगत रूप से तार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। [811 एच; 812 ए-सी]

परंतुक की व्याख्या करने का एकमात्र उचित तरीका 'लेपित कागज' शब्दों को संकीर्ण अर्थों में उसमें उपयोग की जाने वाली अन्य अभिव्यक्तियों के अनुरूप खड़ा करना है। [812 डी]

3. वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत जिसके द्वारा एक सामान्य शब्द को एक सीमित व्याख्या प्राप्त होती है क्योंकि इसका संदर्भ अच्छी तरह से स्थापित है। "नोसिटुर ए सोसाइटिस" अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा आंका जाता है जिसे वह रखती है [810 ए-बी]

हस्तगत मामले के संदर्भ में, इस सिद्धांत को वैध रूप से तैयार किया जा सकता है। हालाँकि, लैटिन मैक्सिम और पूर्ववर्ती यांत्रिक रूप से लागू नहीं होने चाहिए; वे केवल तब तक सहायक होते हैं जब तक वे सामान्य ज्ञान और तर्क के नियमों पर आधारित सिद्धांतों को समग्र रूप से जोड़कर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। [811 ई-एफ]

राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा, [1960] 2 एससीआर 866; रेनबो स्टील्स लिमिटेड बनाम सी. एस. टी., [1981] 2 एस. सी. सी. 141 और लेथांग बनाम कोपेक्स, [1965] 1 क्यू. बी. 232, संदर्भित।

"अमेरिकन पेपर एण्ड पल्प एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित द डिक्शनरी ऑफ पेपर (दूसरा संस्करण), संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं 17 और 18/1989

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली अपील नं. का ई/2123-सी/1987 और ई/2124-सी/1987 क्रम संख्या में 738,739 और 1988 का-सी निर्णय और आदेश दिनांक 3.10.1988 से

के. परासरन, वी. बालचंद्रन और एम. वी. माधव राव अपीलार्थी की ओर से

सॉलिसिटर जनरल अशोक एच. देसाई, सुश्री इंदु मल्होत्रा और पी. परमेश्वरन प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश रंगनाथन, जे. द्वारा पारित किया गया :-

ये केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 35-एल के तहत दो अपीलें हैं। वे मेसर्स रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड (इसके बाद 'निर्धारिती' के

रूप में संदर्भित) के उसके द्वारा निर्मित आर्ट पेपर और क्रोमो पेपर के संबंध में उत्पाद शुल्क से आंशिक छूट के दावे से उत्पन्न होते हैं।

निर्धारिती का खड़की में एक कारखाना है जिसमें विभिन्न प्रकार के कागज और कागज के बोर्ड बनाए जाते हैं। कारखाने में बांस के पल्प का पौधा नहीं है। यह अपशिष्ट कागज और अनाज के भूसे का उपयोग करता है जिन्हें कागज और पेपर बोर्ड के निर्माण के लिए अपरंपरागत कच्चा माल माना जाता है। निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने वाले पल्प में इन असंयोजित कच्चे माल से बने गूदे का वजन 50 प्रतिशत से अधिक होता है।

'पेपर और पेपर बोर्ड' अधिनियम की पहली अनुसूची की मद 17 (1) के तहत आने वाले सामान हैं। 1 मार्च 1984 को उपरोक्त मद के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के तहत दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। उनमें से पहला, 1984 की अधिसूचना संख्या 24 होने के कारण, उपरोक्त मद के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निम्नलिखित तरीके से प्रतिबंधित किया गयाः

क्र. सं.	वर्णन	दर
1.	मुद्रण और लेखन कागज	10 प्रतिशत एडवेलोरम पत्र तथा एक हजार पांच सौ रूपये प्रति मीट्रिक टन

2.	सभी प्रकार के कागज पर जो आम तौर पर क्राफ्ट पेपर के रूप में जाना जाता है (कागज और कागज के बोर्ड क्राफ्ट लाइनर के रूप में जाना जाने वाला प्रकार या नालीदार माध्यम सहित) का पदार्थ के बराबर या उससे 65 ग्राम प्रति वर्गमीटर अधिक	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार तीन सौ 85 रूपये प्रति मीट्रिक टन।
3.	निम्नलिखित पेपर बोर्ड किस्में अर्थात् पल्प बोर्ड डुप्लेक्स बोर्ड और ट्रिपलेक्स बोर्ड।	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार आठ सौ दस रूपये प्रति मीट्रिक टन।
4.	पेपर और पेपर बोर्ड,	दस प्रतिशत एडवेलोरम प्लस एक हजार चार

	क्र.सं. 1 से 3 में निर्दिष्ट के अलावा	सौ तीस रूपये प्रति मीट्रिक टन।

दूसरी अधिसूचना, 1984 की अधिसूचना संख्या 25, वह है जिनसे हम यहाँ सीधे तौर पर संबंधित हैं। यह अनुसूची की मद 17 (1) के तहत आने वाले पेपर और पेपर बोर्डों के संबंध में रियायत प्रदान करता है जो सामग्री (बांस दृढ़ लकड़ी, सॉफ्टवुड, नक्काशी या चिथड़े के अलावा अन्य) से बने गूदे के वजन द्वारा 50 प्रतिशत से कम नहीं वाले गूदे से निर्मित और किसी वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल पर या उसके बाद साफ किया जाता है। निर्धारित रियायती दरें इस प्रकार थीः

क्र.सं.	वर्णन	दर	शर्तें
1 (i)	मुद्रण और लेखन कागज	रूपये 450 प्रति मीट्रिक टन	बशर्ते की कुल मात्रा मंजूरी की मात्रा कागज और कागज पूर्ववर्ती में बोर्ड वित्तीय वर्ष, द्वारा मेन्यूफैक्चरर, एक या अधिक से कारखानों या एक कारखाने से या एक से अधिक मैन्युफैक्चरर
(ii)	सभी प्रकार के कागज आम तौर पर ज्ञात क्राफ्ट पेपर (सहित)	रूपये 450 प्रति मीट्रिक टन	

			का 3000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं था।
(iii)	अन्य	रूपये पांच सौ साठ प्रति मीट्रिक टन	
2 (i)	मुद्रण और लेखन कागज	रूपये 730 प्रति मीट्रिक टन	बशर्ते की कुल मात्रा मंजूरी की मात्रा कागज और कागज पूर्ववर्ती में बोर्ड वित्तीय वर्ष, द्वारा मेन्यूफैक्चरर, एक या अधिक से कारखानों या एक कारखाने से या एक से अधिक मैन्युफैक्चरर का 3000 मीट्रिक टन से अधिक था लेकिन 7500 मैट्रिक टन से कम था।
(ii)	सभी प्रकार के कागज आम तौर पर ज्ञात क्राफ्ट पेपर (सहित) कागज और कागज के बोर्ड अधिक कारखाने या एक से अधिक के रूप में जाना जाता है। मैन्युफैक्चरर क्राफ्ट या नालीदार किसी पदार्थ का माध्यम 65 के बराबर या	रूपये 730 प्रति मीट्रिक टन	

	उससे अधिक ग्राम प्रति वर्गमीटर		
(iii)	अन्य	रूपये नौ सौ प्रति मीट्रिक टन	
3 (i)	मुद्रण और लेखन कागज	रूपये 900 प्रति मीट्रिक टन	बशर्ते की कुल मात्रा मंजूरी की मात्रा कागज और कागज पूर्ववर्ती में बोर्ड वित्तीय वर्ष, द्वारा मेन्यूफैक्चरर, एक या अधिक से कारखानों या एक कारखाने से या एक से अधिक मैन्युफैक्चरर का 7500 मीट्रिक टन से अधिक था लेकिन 16500 मैट्रिक टन से कम था।
(ii)	सभी प्रकार के कागज आम तौर पर ज्ञात क्राफ्ट पेपर (सहित) कागज और कागज के बोर्ड अधिक कारखाने या एक से अधिक के रूप में जाना जाता है। मैन्युफैक्चरर क्राफ्ट या नालीदार किसी पदार्थ का माध्यम 65 के बराबर या	रूपये 900 प्रति मीट्रिक टन	

	उससे अधिक ग्राम प्रति वर्गमीटर		
(iii)	अन्य	एक हजार एक सौ बीस रूपये प्रति मीट्रिक टन	

4. [यह पैरा अधिसूचना सं. 92/84 दिनांकित 18.4.84 ने एक और रियायती दर जोड़ी जहां क्लियर एंस 10,500 से अधिक हो गए लेकिन ऊपर की तरह ही 24,000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं थे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसे यहाँ स्थापित किया जाए] "

हालाँकि, उपरोक्त रियायती दरें अधिसूचना के प्रावधानों में निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन थी। इन प्रावधानों में लिखा हैः

> "बशर्ते कि कारखाने में बांस या लकड़ी का पल्प बनाने के लिए कोई पौधा संलग्न न हो। बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित छूट सिगरेट टिश्यू, ग्लासाइन कागज, ग्रीस प्रूफ पेपर, लेपित कागज (मोम वाले कागज सहित) और 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक के पदार्थ का कागज पर लागू नहीं होगी।"

1985 की एक अन्य अधिसूचना संख्या 45 दिनांकित 17.3.1985 भारत संघ के विवाद के समर्थन में भरोसा किया और इसलिए इसे यहाँ भी

निर्धारित किया जा सकता है। इसने मद 17 (1) के अंतर्गत आने वाला पेपर बोर्ड कागज पर दरें निम्नलिखित तरीके से निर्धारित कींः

क्र. सं.	विवरण	दर
1.	कागज की छपाई और लेखन	
(i)	लेपित कागज	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार पांच सौ रूपये प्रति मीट्रिक टन
(ii)	किसी पदार्थ का जो 25 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक न हो।	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार पांच सौ और पांच रूपये प्रति मीट्रिक टन
(iii)	अन्य	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार पांच सौ पांच रूपये प्रति मीट्रिक टन।
2	आम तौर पर सभी प्रकार के जिन्हें क्राफ्ट पेपर के रूप में जाना जाता है सहित	दस प्रतिशत एडवलोरम तथा एक हजार पांच सौ पिच्यासी रूपये प्रति मीट्रिक टन

	(कागज और कागज के बोर्ड) ओ.टी. क्राफ्ट के रूप में जाना जाने वाला प्रकार (लाइनर या नालीदार माध्यम) किसी पदार्थ के बराबर या 65 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक	
3.	लेपित कागज (मोम वाला कागज सहित) और किसी पदार्थ का कागज जो पच्चीस ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो, (क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट के अलावा)	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार नौ सौ तीस रूपये प्रति मीट्रिक टन
4.	कांच का कागज,	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार नौ

	सिगरेट, उतक और ग्रीस प्रूफ कागज	सौ तीस रूपये प्रति मीट्रिक टन
5.	निम्नलिखित किस्मों का पेपर बोर्ड अर्थात् पल्प बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड और ट्रिपलेक्स बोर्ड	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हाजर आठ सौ दस रूपये प्रति मीट्रिक टन
6.	क्रम संख्या-1 से 5 में निर्दिष्ट के अलावा अन्य कागज और बोर्ड	दस प्रतिशत एडवेलोरम तथा एक हजार चार सौ तीस रूपये प्रति मीट्रिक टन

ऐसा लगता है कि निर्धारिती ने शुरू में अधिसूचना संख्या 24/84 के संदर्भ में इसके द्वारा निर्मित माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि उसने अधिसूचना संख्या 25/84 द्वारा निर्धारित रियायती दरों का दावा करने के बारे में सोचा है। कंपनी आर्ट पेपर और क्रोमो पेपर का निर्माण कर रही थी। यह आम बात है कि ये दो प्रकार के कागज "प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर" श्रेणी में आते हैं। यह भी सामान्य आधार है कि ये दोनों लेख दूसरे परंतुक में उपयोग किए गए विवरण "लेपित कागज" के तहत भी आते हैं। चूंकि लेपित कागज को

परंतुक द्वारा 1984 की अधिसूचना संख्या 25 के दायरे से बाहर कर दिया गया है, इसलिए उत्पाद शुल्क विभाग ने निर्धारिती को अपने निर्मित सामानों के संबंध में इस रियायत का लाभ उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा इस व्यवहार की पुष्टि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपील लेट ट्रिब्यूनल (सी. ई. जी. ए. टी.) द्वारा भी की गई है। न्यायाधिकरण ने मामले का बहुत संक्षिप्त रूप से निपटारा किया। यह देखा गयाः

> "37. यह हमें दूसरे सवाल पर लाता है कि क्या कला पेपर व क्रोमो पेपर नोटिफिकेशन नंबर 25 वर्ष 1984 के तहत रियायत के हकदार हैं। अपीलार्थियों के तर्कों पर पूरी तरह से विचार किया गया। 1984 की अधिसूचना संख्या 24 को संशोधित को देखा गया। दूसरा परंतुक दूसरों के बीच, लेपित कागज (मोम वाले कागज सहित) को रियायत से बाहर करता है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आर्ट पेपर और क्रोमो पेपर लेपित कागज हैं। यह सही हो सकता है कि ये अन्य दूसरे परंतुक में उल्लिखित कागजात औद्योगिक किस्म के कागज और लेखन और मुद्रण की किस्मों की तरह नहीं हैं। सब एक जैसे हैं। इसलिये हम मानते हैं कि कला और क्रोमो पेपर 1984 की अधिसूचना संख्या 25 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं होगा। (जोर दिया गया)

निर्धारिती न्यायाधिकरण के इस आदेश से व्यथित है और इसलिए वर्तमान अपीलें।

श्री के. परासरन, अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए, एक कौशलपूर्ण बात कहते हैं। वह आग्रह करते हैं कि हालांकि अभिव्यक्ति 'लेपित कागज' का आम तौर पर एक व्यापक अर्थ होता है और इसमें सभी के लेपित कागज शामिल होते हैं। फिर भी इसे उस संदर्भ में एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें यह परंतुक में दिखाई देता है। यह निवेदन किया जाता है कि पेपर के व्यापार में, पेपर मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है, "औद्योगिक पेपर" और "सांस्कृतिक पेपर"। मुद्रण या लेखन के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज को सांस्कृतिक कागज के रूप में माना जाता है। दूसरी ओर, औद्योगिक कागज वह कागज है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिन्हें व्यापक रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि लपेटना, पैकिंग स्वच्छता उपयोग और इसी तरह। यह निवेदन किया जाता है कि हालाँकि अधिसूचना का उद्देश्य अपरंपरागत कच्चे माल से कागज बनाने वाले छोटे कारखानों को रियायत देना था। कुछ प्रकार की रियायत से इनकार करने का निर्णय लिया गया था। इन अपवादों को परंतुक में निर्धारित किया गया है। वे इस प्रकार हैंः (1) सिगरेट टिश्यू, (2) कांच का कागज, (3) ग्रीस प्रूफ पेपर, (4) लेपित कागज (मोम वाले कागज सहित), और (5) 25 ग्राम प्रतिवर्ग मीटर से अधिक के पदार्थ का कागज (जिसे हल्के कागज के

रूप में वर्णित किया जा सकता है)। यह तर्क दिया जाता है कि इन सभी श्रेणियों में एक प्रकार की समानता है। पहली तीन किस्में, अर्थात्, सिगरेट टिश्यू, ग्लासिन पेपर और ग्रीस प्रूफ पेपर औद्योगिक कागज की श्रेणी के तहत आते हैं। इसी तरह, एक पदार्थ का 25 ग्राम से अधिक नहीं। प्रति वर्ग मीटर वजन के कागज का उपयोग हमेशा आैद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह न्यायाधिकरण द्वारा पाया जाता है। 'यह आग्रह किया जाता है कि 'लेपित कागज' को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे से परंतुक में निर्धारित वस्तुएँ औद्योगिक कागज की वस्तुएँ हैं- इसका कारण यह है कि हालांकि 'लेपित कागज', एक व्यापक अर्थ में, सभी शामिल हो सकते हैं लेपित कागज की श्रेणियों में, परंतुक द्वारा रियायत से इनकार केवल औद्योगिक किस्म के अंतर्गत आने वाले लेपित कागज तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'लेपित कागज' शब्द की व्याख्या 'नोसिटूर ए सोसाइटीज' के सिद्धांत को लागू करके या 'एजुस्डेम जेनरिस' सिद्धांत के सादृश्य पर की जानी चाहिए। यह तर्क, प्रस्तुत किया जाता है, दो विचारों द्वारा फिर से सूचित किया जाता है। पहला यह है कि सरकार के पास अपवादों को एक साथ रखने के लिए कुछ विचार या सिद्धांत होना चाहिए और प्रतिपादित सिद्धांत के अलावा कोई अन्य बोधगम्य सिद्धांत नहीं है। दूसरा विचार कोष्ठक में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को 'लेपित कागज' के साथ जोड़ना है। (मोम वाले कागज सहित) "। यह बताया गया है कि मोम वाले कागज का स्पष्ट रूप से अर्थ

लेपित कागज है क्योंकि मोम वाला कागज मोम से लेपित कागज के अलावा और कुछ नहीं है और किसी भी तरह अपवाद द्वारा कवर किया गया होगा। फिर भी यह कहा जाता है कि इसे विशेष रूप से शामिल करना आवश्यक था ताकि इस चित्रण से यह स्पष्ट हो सके कि रियायत से केवल मोम वाले कागज जैसे औद्योगिक कागज को ही निकाला जाता है। कोष्ठक में शब्द, दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति 'लेपित कागज' में पढ़ी जाने वाली सीमा के उदाहरण हैं। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि भले ही परंतुक के शब्दों का व्यापक तरीके से अर्थ लगाया जा सके ताकि सभी प्रकार के लेपित कागज को छूट से इनकार किया जा सके, न्यायालय को कराधान कानूनों के निर्माण के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करना चाहिए कि विषय के पक्ष में एक अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए।

दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी निवेदन करते हैं कि यदि परंतुक के दो संभावित विचार हैं, न्यायालय को न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो दो संभावित और प्रशंसनीय विचारों में से एक को दर्शाता है। परंतुक की व्याख्या पर, सॉलिसिटर जनरल निवेदन करते हैं कि व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जिसके द्वारा 'लेपित कागज' शब्द के स्पष्ट और प्राकृतिक अर्थ को संक्षिप्त किया जा सके और न ही, इस तरह की सीमा की गारंटी देने के लिए संदर्भ में कुछ भी है। वे इस सुझाव का खंडन करते हैं कि व्यावसायिक भाषा में, औद्योगिक और सांस्कृतिक पत्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है। वह इस बात से सहमत

नहीं हैं कि हल्का कागज केवल औद्योगिक कागज हो सकता है और यह 1985 की अधिसूचना की शर्तों को संदर्भित करता है। वह निवेदन करते हैं कि यदि लेपित कागज का अर्थ केवल औद्योगिक कागज है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा तर्क दिया गया है, तो कोष्ठक में पूरी तरह से अनावश्यक अभिव्यक्ति थी। वह निवेदन करता है कि लेपित कागज और संवर्धित कागज के बीच अंतर है। चूंकि मोम वाला कागज इनमें से किसी भी श्रेणी में आ सकता है, किसी के यह तर्क देने की संभावना थी कि मोम से भरा हुआ कागज 'लेपित कागज' नहीं है; इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक जोड़ना आवश्यक हो गया कि दोनों प्रकार परंतुक के उद्देश्यों के लिए 'लेपित कागज' होंगे। वह इन कारणों से प्रस्तुत करता है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही था और अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

हमने दोनों पक्षों की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर विचार किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी की याचिका में बल है। ऊपर जिन तीनों अधिसूचनाओं को हमने निकाला है, वे एक ओर मुद्रण और लेखन कागज और दूसरी ओर अन्य प्रकार के कागज के बीच अंतर दर्शाती हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि मुद्रण और लेखन के कागज के पर शुल्क आम तौर पर कागज की अन्य किस्मों की तुलना में कम होता है। हालांकि कागज को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा एक वर्गीकरण औद्योगिक पेपर और सांस्कृतिक

पेपर के बीच है। अमेरिकन पेपर एंड पल्प एसोसिएशन (दूसरा संस्करण) द्वारा प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ पेपर में निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैः

> "औद्योगिक पत्र-एक बहुत ही सामान्य शब्द जिसका उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित पत्रों को सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उनके विपरीत के रूप में इंगित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, कागज लिखते और छापते समय बिल्डिंग पेपर, इंसुलेटिव पेपर, मैचिंग पेपर आदि को औद्योगिक पेपर माना जाएगा। जबकि लेखन व मुद्रण पेपर सांस्कृतिक पत्र होंगे।"

अब परंतुक अधिसूचना संख्या 25/84 द्वारा कुछ प्रकार के कागजातों को दी गई रियायत से इनकार करता है। यह सच है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच शुल्क की दरों में भिन्नता के लिए कोई सावधानीपूर्वक कारण हमेशा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है या खोजा नहीं जा सकता है और समान रूप से व्यवहार किए जाने वाले सामानों के एक समूह के संबंध में कुछ सामान्य धागे की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से वर्गीकरण को तर्कहीन या मनमाना नहीं बना सकती है। लेकिन, एक ही समय में, कोई भी वैध रूप से यह मान सकता है कि किसी समूह को सहमति देने से इनकार करना समूह में सभी वस्तुओं के लिए किसी पहलू या सुविधा के आधार पर आगे बढ़ता है। यदि ऐसे सिद्धांत की कल्पना की जा सकती है

जिससे सभी वस्तुओं के समावेश को तर्कसंगत बनाया जा सके, तो उस सिद्धांत के अनुसार अधिसूचना के निर्माण को प्रभावी बनाना काफी उचित होगा। यह वही है जो अपीलार्थी ने करने का प्रयास किया है और हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि सुझाए गए अपवादों का अनुपात, कृत्रिम या दूरगामी होने की जगह, एक प्रशंसनीय और संभावित है जो सरकार के दिमाग में हो सकता था और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिसूचना की रियायत को पाँच प्रकार के कागज के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। उनमें से तीन, निस्संदेह और निर्विवाद रूप से, औद्योगिक कागज की किस्में हैं। यह वास्तव में एक सामान्य आधार है और यह डिक्शनरी में परिभाषाओं के संदर्भ में भी इसका समर्थन किया गया है कागज की संख्या और अन्य जो यहाँ निर्धारित करना अनावश्यक है। चौथा वह है जिसे हमने 'हल्के कागज' के रूप में संदर्भित किया है जो एक विशेष वजन से अधिक नहीं है। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह भी केवल औद्योगिक कागज है। इस तर्क के समर्थन में, संदर्भ डिक्शनरी ऑफ पेपर में संलग्न तालिकाओं में दिया गया जो दर्शाता है कि 26 ग्राम प्रति वर्ग मीटर कम वजन का मुद्रण और लेखन कागज नहीं हो सकता है। यह भी बताया गया है कि न्यायाधिकरण ने भी इसके आदेश के पैरा 37 में इसी आशय का निष्कर्ष दिया है। दूसरी ओर विद्वान सॉलिसिटर जनरल इंगित करते हैं कि क्रम संख्या 1 (ii) 1985 अधिसूचना स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाती है कि

"मुद्रण और लेखन पेपर 25 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक का नहीं हो सकता है। यह निवेदन किया गया है कि वर्गीकरण पूरी तरह से अवास्तविक आधार पर आगे बढ़ता है और ऐसा कोई मुद्रण और लेखन कागज अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हम मान नहीं सकते कि 1985 की अधिसूचना गलत आधार पर आगे बढ़ती है। हमारे उद्देश्यों के लिए, इस मामले में रिकॉर्ड के आधार पर, यह लेने के लिए पर्याप्त है कि हल्का कागज, मोटे तौर पर, बिना औद्योगिक कागज के है। पूरी तरह से सभी संभावनाओं को छोड़कर कि इसका उपयोग कभी-कभी सांस्कृतिक उद्देश्य से भी किया जाता है। 1985 की अधिसूचनाओं में निर्धारित वर्गीकरण भी आग्रह किए गए विवादों को कुछ समर्थन देता है। हम जिन पाँच प्रकार के कागज से संबंधित हैं, वे अधिसूचना के क्रम संख्या 3 व 4 में पाए जाते हैं और क्रम संख्या। 1 और 3 सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले लेपित कागज और हल्के कागज के बीच एक अंतर को दर्शाते हैं (मद संख्या 1) और जिसका उपयोग अन्य (औद्योगिक) उद्देश्यों के लिए किया जाता है (मद संख्या 4)। इस आधार पर, यह स्पष्ट है कि कागज की पाँच किस्मों में से चार किस्मों में जिनमें रियायत के लाभ से इनकार किया गया है औद्योगिक कागज प्रतीत होता है। वास्तव में, जैसा कि भारत संघ के लिए आग्रह किया गया है, अगर इनमें से केवल तीन वस्तुएं औद्योगिक किस्म की हैं, जबकि अन्य दो भी हो सकती हैं, तो भी यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा (हालांकि, थोड़ा कम प्रशंसनीय हो सकता है)

कि उन दो श्रेणियों में आने वाले केवल औद्योगिक कागज को वर्गीकरण में समझने का इरादा है, न कि बिना किसी पता लगाने योग्य कारण के, कि अकेले इन दो किस्मों के सभी कागज रियायत से बाहर हैं। इसलिए, हम सोचते हैं कि अपीलकर्ता यह प्रस्तुत करने में दृढ़ हैं कि परंतुक में 'लेपित कागज' अभिव्यक्ति को उस संदर्भ से रंग लेना चाहिए जिसमें इसे नियोजित किया गया है और इसकी शाब्दिक व्याख्या की तुलना में एक व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए, जो अपने व्यापक अर्थों में, सभी लेपित कागज, औद्योगिक या औद्योगिक को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो सकती है।

वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत जिसके द्वारा एक सामान्य शब्द अपने संदर्भ के कारण एक सीमित व्याख्या प्राप्त करता है सुस्थापित है। जिस संदर्भ के साथ हमारा संबंध है, हम "नास्सिटुर ए सोसाइटिस" सिद्धांत पर कानूनी रूप से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि "किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा आंका जाता है जिसे वह रखती है।" जे. गजेंद्रगडकर ने राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा, [1960] 2 एससीआर 866 में नियम के दायरे की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में कीः

> "मैक्सवेल के अनुसार, इस नियम का अर्थ है कि, जब दो या दो से अधिक शब्द समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है और समझा जाता है

कि उनका उपयोग उनके संज्ञानात्मक अर्थों में किया जाता है। वे एक-दूसरे से अपना रंग लेते हैं, यानी जितना अधिक सामान्य होता है, उतना ही कम सामान्य के समान एक अर्थ तक सीमित होता है। एक ही नियम इस प्रकार अंतर है "शब्दों और वाक्यांशों" (वीओ। XIV, पी। 207): " संबद्ध शब्द एक दूसरे से अपना अर्थ एक समाज के सिद्धांत के तहत लेते हैं, जिसका दर्शन यह है कि एक संदिग्ध शब्द का अर्थ उन शब्दों के अर्थ के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं; इस तरह का सिद्धांत एजुस्डेम जेनरिस की तुलना में व्यापक है। वास्तव में अक्षर उक्ति "केवल एक चित्रण या व्यापक उक्ति नोस्किटुर ए सोसाइटिस का विशिष्ट अनुप्रयोग है"। तर्क यह है कि कुछ आवश्यक विशेषताएं या विशेषताएँ हमेशा "बिजनेस एण्ड ट्रेड" शब्दों के साथ जुड़ी होती हैं जैसा कि लोकप्रिय और पारंपरिक अर्थों में समझा जाता है, और यह इन एट्रीब्यूट्स का रंग है जो परिभाषा में उपयोग किए गए अन्य शब्दों द्वारा लिया जाता है, हालांकि उनका सामान्य महत्व बहुत व्यापक हो सकता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज केवल निर्माण का एक नियम है और यह उन मामलों में प्रबल नहीं हो सकता

है जहां यह स्पष्ट है कि व्यापक शब्दों का उपयोग जानबूझकर किया गया है ताकि परिभाषित शब्द का दायरा तदनुसार व्यापक होता है। यह केवल वहाँ है जहाँ संकीर्ण महत्व के शब्दों के साथ व्यापक शब्दों को जोड़ने में विधानमंडल का इरादा संदिग्ध है, या अन्यथा स्पष्ट नहीं है कि निर्माण के वर्तमान नियम को उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है। इसे वहाँ भी लागू किया जा सकता है जहाँ व्यापक महत्व के शब्दों का अर्थ स्पष्ट है; लेकिन, जहाँ व्यापक शब्दों का उपयोग करने में विधानमंडल का उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त है, वहाँ विचाराधीन निर्माण के नियम पर दवाब नहीं डाला जा सकता।

यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में कई संदर्भों में लागू किया गया है जहां न्यायालय अपने दिमाग में स्पष्ट है कि विचाराधीन शब्द का बड़ा अर्थ उस संदर्भ में नहीं किया जा सकता था जिसमें इसका उपयोग किया गया है। यहां चर्चा की आवश्यकता के लिए मामले बहुत अधिक हैं। उनमें से किसी एक को उदाहरण के माध्यम से संदर्भित करना पर्याप्त होना चाहिए। रेनबो स्टील्स लिमिटेड बनाम। सी. एस. टी., [1981] 2 एस. सी. सी. 141 इस न्यायालय को कर लगाने वाले शुल्क में प्रविष्टि के संदर्भ में 'पुराने' शब्द का अर्थ समझना था जो इस प्रकार हैः

"पुरानी, बेकार, अनुपयोगी या पूर्ण मशीनरी,अपशिष्ट उत्पादों सहित दुकानें या वाहन ....."

हालांकि शुल्क मद व्यापक शब्द 'पुराना' के उपयोग के साथ शुरू हुआ, लेकिन अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "प्रवेश में आने वाली पुरानी मशीनरी के दायरे में आने के लिए, मशीनरी इस अर्थ में पुरानी मशीनरी होनी चाहिए कि यह गैर-कार्यात्मक या गैर-उपयोग योग्य हो गई है"। दूसरे शब्दों में, न केवल तंत्र की आयु, जो व्यापक अर्थों में प्रासंगिक होगी, बल्कि उसके बाद के शब्दों द्वारा इंगित किए गए समान यंत्र की स्थिति को क़ानून के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक माना गया था।

डिप्लोक सी.जे. द्वारा एक समाज के सिद्धांत का वर्णन "विश्वासघाती जब तक कि कोई" उन समाजों को नहीं जानता जिनसे वे संबंधित हैं "के रूप में किया गया है, (लेटांग बनाम कोपेक्स, [1965] 1 क्यू. बी. 232)। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी को बहकाया नहीं जाना चाहिए लेबल और लैटिन अधिकतम तब होता है जब व्याख्या किया जाने वाला शब्द स्पष्ट होता है और इसका व्यापक अर्थ होता है। हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि इन सिद्धांत और सिद्धांत को यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए; वे केवल उस हद तक सहायक हैं जब वे सामान्य ज्ञान और तर्क के नियमों पर आधारित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करके मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क

के कलेक्टर बनाम में समझाया गया है। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, [1989] 1 एस. सी. सी. 345 पी. 357 और टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई., [1989] 4 एस. सी. सी. 541 पी. 545-6 किसी भी अधिसूचना के दायरे की व्याख्या करने में, न्यायालय को सबसे पहले अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। इसके सभी भागों को उस उद्देश्य की सहायता के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि अपमान के रूप में। इस मामले में, अधिसूचना का उद्देश्य और उद्देश्य छोटे पैमाने के कारखानों को एक संघ प्रदान करना है जो असंबद्ध कच्चे माल के साथ कागज का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता हैः क्या परंतुक में निर्धारित अपवादों को लागू करके कोई विशेष उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था? पूर्व पर आगे बढ़ने के बजाय यह देखते हुए कि कर कानून में किसी भी कारण को देखना आवश्यक नहीं है, परंतुक के शब्दों पर करीब से नज़र डालना आवश्यक है। यदि परंतुक में केवल 'लेपित कागज' का उल्लेख किया गया था, तो कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। इससे परे देखने और अटकलों में प्रवेश करने का कोई औचित्य नहीं था अधिसूचना को रद्द करने के लिए केवल 'कोटेड' को छूट देने के बारे में सोचना चाहिए था लेकिन अधिसूचना में एक नहीं बल्कि वस्तुओं के एक समूह को शामिल किया गया है। यदि समूह में उल्लिखित आइटम पूरी तरह से भिन्न थे और उनके माध्यम से फिर से किसी भी समानता को देखना असंभव है, यह अपवादों को उनका सबसे वृहद अर्थ देने की

अनुमति हो सकती है। लेकिन जब उनका दौरा-निस्संदेह, उनमें से कम से कम तीन को एक बोधगम्य वर्गीकरण के तहत लाया गया है और इसकी कल्पना भी की जा सकती है कि सरकार ने सोचा होगा कि ये छोटे पैमाने के कारखानों को अनुध्यात रियायत के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। अधिसूचना जहाँ वे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कागज का निर्माण करते हैं निर्धारित सीमा में एक उद्देश्य है और कोई नहीं है तर्कसंगत रूप से इस वर्गीकरण पर आधारित परंतुक के आधार पर तार्किक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारी राय में, एकमात्र कारण प्रावधान की व्याख्या करने का सक्षम तरीका 'लेपित कागज' शब्दों को एक संकीर्ण अर्थ में अन्य अभिव्यक्तियों के अनुरूप समझना है।

हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें दूसरे हमारे सामने आग्रह किए गए विवाद पर विचार करना अनावश्यक हैः (i) क्या शब्द "(वैक्स सहित कागज)" शब्द उस सीमा का संकेत देते हैं जिसे शब्द "लेपित कागज" पर रखने की मांग की गई है या वे केवल इसे स्पष्ट करने के लिए हैं कि मोम से भरा हुआ कागज भी रियायत का हकदार नहीं होगा; और (ख) यदि अधिसूचना की दो समान रूप से प्रशंसनीय व्याख्याएँ संभव है तब जो विषय के पक्ष में है बरकरार रखी जानी चाहिए या न्यायाधिकरण के निर्वचन की पुष्टि की जानी चाहिए।

ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार करते हैं कि दूसरे परंतुक में 'लेपित कागज' केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए लेपित को संदर्भित करता है न कि लेखन व मुद्रण पेपर की लेपित किस्मों को। न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलांट अधिसूचना नं. 25/84 में निर्दिष्ट रियायती दरों का हकदार है

अपीलों की अनुमति दी जाती है। लेकिन हम लागत के बारे में कोई आदेशनहीं देते हैं।

अपील की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी असीम कुलश्रेष्ठ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।